International Journal of Education and Science Research Review
E-ISSN 2348-6457
Volume-8, Issue-3 May-June- 2021
P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org Email- editor@ijesrr.org

भारत में सहकारी आंदोलन का इतिहास

महेंद्र शेखावत
वाणिज्य विभाग
महाराज विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी

डॉ स्वेच्छा मित्तल
, निर्देशिका

डॉ गुरप्रीत कौर
, सह निर्देशिका

सार

एक सहकारिता संगठन का एक रूप है जो भारत सहित विकासशील देशों में व्यापक रूप से प्रचलित है। ग्रामीण विकास के एक साधन के रूप में इसमें काफी संभावनाएं हैं। एक नैतिक मानदंड के रूप में सहयोग की प्राचीन काल से ही दुनिया भर में प्रशंसा की जाती रही है। सामाजिक व्यवहार के एक तरीके के रूप में, यह एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाने वाली अनगिनत गतिविधियों में प्रकट होता है।

भारत में सहकारी साख समिति अधिनियम के लागू होने के परिणामस्वरूप 1904 में संगठन के सहकारी रूप का जन्म हुआ। इसके बाद, एक अधिक व्यापक अधिनियम, सहकारी समिति अधिनियम, 1912 में अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम में, अन्य बातों के साथ–साथ, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के पद के निर्माण के लिए, विभिन्न उद्देश्यों के लिए सहकारी समितियों के पंजीकरण के लिए प्रदान किया गया, और लेखापरीक्षा। 1919 में प्रभावित मोंटेक–चेम्स फोर्ट रिफॉर्म्स के तहत, सहकारिता एक प्रांतीय विषय बन गई और प्रांतों को अपने स्वयं के सहकारी कानून बनाने के लिए अधिकृत किया गया।

भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, सहकारी समितियों को राज्य विषय के रूप में माना जाता था। एक से अधिक प्रांतों की सदस्यता वाली सहकारी समितियों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए, भारत सरकार ने बहु–इकाई सहकारी समिति अधिनियम, 1942 अधिनियमित किया। बाद में एक अधिक व्यापक केंद्रीय कानून, बहु–राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984, एक ही प्रकार की सहकारी समितियों को नियंत्रित करने वाले विभिन्न कानूनों को समेकित करने की दृष्टि से संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था।

मुख्य शब्द

सहकारी, समिति, ग्रामीण

भूमिका

अनादिकाल से भारत ग्राम समुदायों का देश रहा है, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। इसके 700 मिलियन से अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और इसके ग्रामीण क्षेत्र ने 1993–94 की कीमतों पर कारक लागत पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 29 प्रतिशत योगदान दिया है, भारत के सामाजिक–आर्थिक विकास की कोई रणनीति नहीं है जो ग्रामीण लोगों की उपेक्षा करती है और ग्रामीण क्षेत्र सफल हो सकते हैं। इसलिए, ग्रामीण विकास भारत में समग्र विकास के लिए अनिवार्य है।

शब्द, ग्रामीण विकास, व्यापक शब्द विकास का एक उपसमुच्चय है, जो एक व्यक्तिपरक और मूल्य–भारित अवधारणा है और इसलिए इसे परिभाषित करना मुश्किल है। हम इसे कैसे भी परिभाषित करें, विकास पूरी दुनिया में व्यक्तियों, परिवारों, समुदायों और राष्ट्रों का सार्वभौमिक रूप से पोषित लक्ष्य है। ग्रामीण विकास शब्द ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास को दर्शाता है जैसा कि ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार से पता चलता है।

इस अर्थ में, यह एक व्यापक और बहुआयामी प्रक्रिया और घटना है। इसमें कृषि और संबद्ध गतिविधियों, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों और शिल्प, सामाजिक–आर्थिक बुनियादी ढाँचे, सामुदायिक सेवाओं और सुविधाओं, और सबसे बढ़कर, ग्रामीण क्षेत्रों में मानव संसाधनों का विकास शामिल है।

वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, आय वितरण में सुधार, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता, और संसाधनों, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, रोजगार के अवसरों तक समान पहुंच जैसे वांछनीय सामाजिक उद्देश्यों के गैर–घटते सेट के रूप में विकास की अवधारणा की जा सकती है। और न्याय।

सरकारी एजेंसियों, एकमात्र स्वामित्व, साझेदारी, कंपनियों, सहकारी समितियों और धर्मार्थ ट्रस्ट जैसे संगठनों के कई रूप हैं जो वास्तव में भारत में ग्रामीण लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और कर रहे हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप को 19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में देखा जा सकता है। तब से, सरकार ने कृषि और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किए हैं और हर तरह से ग्रामीण विकास की सबसे बड़ी एजेंट है।

सहकारी समितियों ने भारत में कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेष रूप से ऋण, प्रसंस्करण और विपणन के क्षेत्र में। गुजरात की डेयरी सहकारी समितियाँ और महाराष्ट्र की चीनी सहकारी समितियाँ सहकारी समितियों के अच्छे उदाहरण हैं जो ग्रामीण विकास को बढ़ावा दे सकती हैं और बनाए रख सकती हैं।

गांधीजी ने ग्रामीण विकास के साधन के रूप में सहकारिता को एक महान गुण के रूप में देखा। उन्होंने सहकारी खेती को बढ़ावा देने और इस तरह भूमि जोत के आगे विखंडन को रोकने के लिए कृषि के क्षेत्र में सहकारी समितियों को विशिष्ट भूमिकाएँ सौंपी। उन्होंने अन्य प्रकार की सहकारी समितियों जैसे कि क्रेडिट सहकारी समितियों, बुनकरों और कताई सहकारी समितियों और डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना की भी वकालत की।

1904 के अधिनियम के अधिनियमन के साथ, पहली सहकारी ऋण समिति 8 मई, 1905 को धारवाड़ जिले के गदग तालुका में तत्कालीन बंबई राज्य में कंगिनहाल कृषि ऋण सहकारी के नाम से पंजीकृत की गई थी। 1911 तक, 305,060 की सदस्यता के साथ पंजीकृत सोसायटियों की संख्या बढ़कर 5321 हो गई। इसके बाद, 1904 के अधिनियम को 1912 में पारित एक और व्यापक आधार के साथ बदल दिया गया, गैर–क्रेडिट सहकारी समितियों के लिए भी पंजीकरण शुरू किया गया।

भारत में सहकारी आंदोलन का इतिहास

सुधार अधिनियम 1919 में पारित किया गया था, जब सहकारिता राज्यध्प्रांतीय विषय बन गई थी। 1919 से 1929 का दशक अनियोजित विस्तार और कुछ पुनर्गठन का काल था। 1930ध्31–1937ध्38 की अवधि के दौरान, आंदोलन में कई परिवर्तन हुए। यह अवधि महान मंदी के लिए जानी जाती है, जो मुख्य रूप से हमारी पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था और अशांत राजनीतिक माहौल के कारण भारत में सहकारी समितियों के लिए एक बड़ा झटका था।

सहकारी समितियों के ऋणों का बकाया 1930–31 में 39ः से बढ़कर 1937–38 तक 63ः हो गया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध (1939 से 1946) कृषकों के लिए एक वरदान के रूप में आया, क्योंकि कृषि वस्तुओं की कीमतों में काफी वृद्धि हुई और सहकारी समितियों का पुनरुद्धार हुआ। किसानों की चुकाने की क्षमता में काफी वृद्धि हुई, वे अपने पुराने ऋणों को चुकाने में सक्षम हुए और बकाया 1937–38 में 63% से घटकर 1945–46 में 39% हो गया। इस अवधि को रिकवरी पीरियड माना जाता है।

अगस्त 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, सहकारी समितियों ने सामाजिक–आर्थिक विकास के एक साधन के रूप में अधिक महत्व ग्रहण किया और भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का एक अभिन्न अंग बन गई।

पहली पंचवर्षीय योजना (1950–51 से 1955–56) में इस बात पर जोर दिया गया था कि सभी कृषक परिवारध्परिवार प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के सदस्य के रूप में शामिल हो सकते हैं। बदले में, ये सोसायटियां उनकी जरूरतों का ध्यान रखेंगी और किसानों और कारीगरों के हितों की रक्षा करेंगी। इस योजना अवधि के दौरान, सहकारी समितियों की संख्या और सदस्यता 1950–51 में क्रमशः 115,462 और 5.2 मिलियन से बढ़कर 1955–56 तक क्रमशः 159,939 और 7.8 मिलियन हो गई।

वर्ष 1951 में, त्ठप् ने अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति के रूप में जानी जाने वाली एक समिति की स्थापना की और इसकी रिपोर्ट 1954 में प्रकाशित हुई। उस समय, मुख्य जोर व्यवहार्यता अवधारणा पर था। यह देखा गया कि केवल 20% सहकारी समितियाँ अपने सीमित संचालन के कारण आर्थिक रूप से व्यवहार्य पाई गईं और यह सिफारिश की गई कि अधिक व्यवसाय प्राप्त करने के लिए बड़े आकार की सहकारी समितियों का गठन किया जाना चाहिए।

यह भी सिफारिश की गई कि 51% की सीमा तक शेयर पूंजी वाली सरकार को सहकारी समितियों में भागीदार बनने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा, यह अनुशंसा की गई कि लघु और मध्यम अवधि के ऋणों के लिए ऋण वितरण प्रणाली त्रिस्तरीय हो और भूमि विकास बैंकों के माध्यम से दीर्घकालिक ऋण की व्यवस्था की जाए।

साथ ही, ग्रामीण कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से निर्देशित करने और कार्यान्वित करने के लिए गांव से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक संस्थानों का एक मजबूत नेटवर्क विकसित करने के लिए एक प्रभावी सहकारी प्रशिक्षण प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया गया। सौभाग्य से, सरकार ने समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया।

पंचवर्षीय योजनाएँ (दूसरी से पाँचवीं तक)

दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956–57 से 1960–61) का व्यापक उद्देश्य समाज के समाजवादी स्वरूप को विकसित करना था। योजना में नियोजित विकास की योजना के एक भाग के रूप में एक सहकारी क्षेत्र के निर्माण की परिकल्पना की गई थी। इसके बाद, राष्ट्रीय सहकारी संकल्प 1958 ने सिफारिश की कि ऋण और विपणन को जोड़ा जाना चाहिए और ग्राम स्तर पर बड़े आकार की समितियों को पुनर्गठित करने के बजाय सेवा समितियों को संगठित करने का संकल्प लिया गया।

इस विषय को वैकुंठ मेहता समिति को भेजा गया, जिसने दोनों पहलुओं का अध्ययन करने के बाद मध्यम मार्ग की सिफारिश की, यानी उनके लिए व्यवहार्य और प्रबंधनीय होने के लिए मध्यम आकार के समाजों का संगठन। तीसरी पंचवर्षीय योजना श्रमिकों, उपभोक्ता सहकारी समितियों और रोजगार सृजन पर केंद्रित थी।

तदनुसार, आठ विभिन्न प्रकार की समितियाँ गठित की गईं। चौथी योजना (1969–70 से 1973–74) में सहकारी गतिविधियों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया गया था। इस अवधि के दौरान, शिक्षा और प्रशिक्षण सेटअप को मजबूत किया गया था। साथ ही चौथी योजना के संदर्भ में ग्रामीण ऋण आपूर्ति की समीक्षा के लिए अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति नियुक्त की गई।

अपने निष्कर्षों के आधार पर, समिति ने (ए) ग्रामीण ऋण का पुनर्गठन, (बी) प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता, (सी) एसएफडीए, एमएफडीए, और आईएडीपी एजेंसियों की स्थापना और (डी) पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करने पर जोर दिया सहकारी और वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से कृषि के लिए ऋण। पांचवीं पंचवर्षीय योजना ने सहकारी समिति को कमजोर वर्गों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थागत ढांचा माना, विशेष रूप से प्रासंगिक इनपुट प्रदान करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रबंधन के लिए।

1977 में, 1958 के नीति संकल्प की समीक्षा उस अवधि के दौरान हुए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के संदर्भ में की गई थी। संकल्प, जिसे अब अपनाया गया है, ने सिफारिश की है कि ए) ग्रामीण विकास के लिए एक मजबूत और व्यवहार्य

सहकारी प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए, बी) उपभोक्ता सहकारी आंदोलन को सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए विकसित किया जाना चाहिए, सी) सहकारी समितियों को कार्य करने के लिए बनाया जाना चाहिए विकेन्द्रीकृत श्रम–गहन और ग्रामीण उन्मुख आर्थिक विकास के प्रमुख उपकरणों में से एक, और घ) सहकारी समितियों के पेशेवर प्रबंधन को यथाशीघ्र स्थापित किया जाना चाहिए।

पंचवर्षीय योजनाएँ (छठी से नौवीं)

इन योजनाओं के दौरान मुख्य जोर था) अपने सदस्यों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को बहुउद्देश्यीय समितियों के रूप में कार्य करने के लिए मजबूत करना, इ) पेशेवर जनशक्ति का विकास, और ब) मौजूदा सहकारी समितियों का पुनर्परीक्षण नीतियां और प्रक्रियाएं यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यक्रम वास्तव में ग्रामीण गरीबों की आर्थिक स्थिति में सुधार करते हैं।

इस दौरान कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया। सातवीं योजना में सहकारी समितियों की आवश्यकता पर बल दिया गया था क) खाद्य उत्पादन में वृद्धि, ख) रोजगार के अवसर पैदा करना, और ग) आम तौर पर उत्पादकता में वृद्धि।

इसने विविध गतिविधियों के महत्व और सहकारी आंदोलन के प्रयासों के समेकन की ओर इशारा किया। नौवीं योजना अवधि के दौरान, इस बात पर बल दिया गया कि सभी सहकारी समितियों को अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए। नतीजतन, बहु राज्य सहकारी समिति विधेयक पारित किया गया और सहकारी समितियों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एक नया अधिनियम 2002 लागू हुआ। इस काल की दूसरी उपलब्धि यह थी कि नई सहकारिता नीति की घोषणा की गई। अन्य बातों के अलावा, इसने सहकारी समितियों के योगदान को मान्यता दी और ग्रामीण विकास में उनकी भविष्य की भूमिका की ओर भी इशारा किया।

दूध सहकारिता

गुजरात के खेड़ा जिले में खेड़ा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, जिसे आम तौर पर अमूल के नाम से जाना जाता है, की छत्रछाया में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के विकास और विकास ने पचास और साठ के दशक के दौरान एक साधन के रूप में सहकारी समितियों की क्षमता का प्रदर्शन किया।

अक्टूबर 1964 में अमूल और एक ग्रामीण दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का दौरा करने के बाद, भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री, आनंद मॉडल की उपयुक्तता के बारे में आश्वस्त हुए और भारत सरकार को वर्गीज की अध्यक्षता में एक संगठन स्थापित करने की सलाह दी। कुरियन भारत में आनंद पैटर्न डेयरी सहकारी समितियों को दोहराने के लिए।

नतीजतन, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में आनंद में मुख्यालय के साथ की गई थी। एनडीडीबी ने देश में आनंद पैटर्न सहकारी समितियों को दोहराने के लिए ऑपरेशन फ्लड नामक एक कार्यक्रम तैयार किया। शायद दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम है। 1 जुलाई, 1970 को 18 चुनिंदा मिल्क शेड्स में लॉन्च किया गया, अब भारत में 175 मिल्कशेड को कवर करता है है।

दूध और दुग्ध उत्पादों की खरीद, प्रसंस्करण, परिवहन, भंडारण और विपणन के लिए बुनियादी ढांचे को बनाने और मजबूत करने के लिए 2000 करोड़, पशु आहार के संयोजन के लिए, पशु स्वास्थ्य देखभाल और प्रजनन सेवाओं के प्रावधान के लिए, डेयरी मशीनरी, उपकरण के निर्माण के लिए और अन्य सामग्री, और ग्रामीण प्रबंधकों, किसानों और सहकारी डेयरी संघों और संघों के निदेशक मंडल के सदस्यों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए। मार्च 1996 तक, भारत में लगभग 72,000 आनंद पैटर्न दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियाँ कार्यरत थीं, जिनकी कुल सदस्यता 9 मिलियन से अधिक दुग्ध उत्पादकों की थी, जो देश के 175 दुग्धशालाओं में फैले हुए थे।

चीनी सहकारी समितियाँ

भारत में सहकारी चीनी कारखाने स्वतंत्रता के बाद के विकास हैं, हालांकि चार ऐसे कारखाने 1933 और 1935 के बीच स्थापित किए गए थे। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के श्रीरामपुर तालुका में 1950–51 में स्थापित की गई प्रवरा सहकारी चीनी फैक्ट्री एक साबित हुई। उत्कृष्ट सफलता और गन्ना उत्पादकों और महाराष्ट्र सरकार को राज्य में इसी तरह के कारखाने स्थापित करने के लिए प्रेरित किया।

भारत सरकार ने लाइसेंस जारी करते समय सहकारी चीनी मिलों को निजी और ज्वाइंट स्टॉक मिलों की तुलना में वरीयता देकर प्रोत्साहित करने की नीति भी अपनाई। राज्य सरकार ने सहकारी चीनी कारखानों को उनकी शेयर पूंजी में योगदान देकर सहायता की लेकिन उन्हें कोई सब्सिडी या कोई अन्य विशेषाधिकार नहीं दिया गया।

दो प्रसिद्ध सार्वजनिक हस्तियां, डी.आर. गाडगिल और वैकुंठ एल मेहता ने राज्य में सहकारी चीनी मिलों की सहायता और मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुजरात की आनंद–पैटर्न डेयरी सहकारी समितियों की तरह, महाराष्ट्र की चीनी सहकारी समितियों को भी ग्रामीण विकास के साधन के रूप में सफल माना जाता है। भारत में अब 280 से अधिक सहकारी चीनी कारखाने हैं, जो देश के कुल चीनी उत्पादन का लगभग 60 प्रतिशत है।

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन सहकारी समितियाँ

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन सहकारी समितियाँ भारत में अपेक्षाकृत हाल ही में उत्पन्न हुई हैं, लेकिन वे बंजर भूमि, मत्स्य पालन, जल और लघु वन उपज जैसे नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों के भागीदारी प्रबंधन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा

रही हैं। बुनियादी ढांचे और वित्त दोनों के संदर्भ में संस्थागत समर्थन की कमी भी उनके खराब विकास के लिए एक महत्वपूर्ण सहायक कारक है। कुछ समय से मत्स्य सहकारी समितियों ने कुछ क्षेत्रों में अच्छे परिणाम दिए हैं और मछुआरों को बिचौलियों के शोषण से बचाया है और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार किया है, लेकिन मत्स्य सहकारी समितियों का समग्र प्रभाव उत्साहजनक नहीं है।

उपभोक्ता सहकारी समितियाँ

भारत में उपभोक्ता सहकारी समितियों का भी 1904 में एक लंबा इतिहास रहा है जब तमिलनाडु में भारत की पहली प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी समिति की स्थापना की गई थी। आजादी से पहले, सूखे, बाढ़, अकाल और युद्धों के समय उनकी उपस्थिति अधिक दिखाई देती थी, जब वे प्रभावित लोगों को आवश्यक वस्तुओं के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे।

1947 में स्वतंत्रता के बाद उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था में उचित महत्व दिया गया था। पंचवर्षीय योजनाओं ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए एक संस्थागत वाहन के रूप में उपभोक्ता सहकारी समितियों की पहचान की है। उपभोक्ता सहकारी समितियों के पास अब एक चार स्तरीय संरचना है जिसमें निम्नतम (ग्राम) स्तर (28,290) पर प्राथमिक समितियां, जिला स्तर पर थोकध्केंद्रीय स्टोर (696), राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ (29) शामिल हैं। और एक राष्ट्रीय महासंघ। सभी उपभोक्ता सहकारी समितियों की कुल सदस्यता लगभग 1.65 मिलियन और कार्यशील पूंजी 45000 मिलियन रुपये होने का अनुमान है।

हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर खुदरा वितरण में उपभोक्ता सहकारी समितियों का हिस्सा केवल 2 प्रतिशत है, उनका महत्व आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने, उचित मूल्य पर उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, विशेष रूप से कमी के समय में, रोजगार के अवसर पैदा करने में निहित है। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और विशेषाधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

लेकिन उनके द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, उपभोक्ता सहकारी समितियाँ अपने वित्तीय आधार का निर्माण करने में विफल रही हैं, जिसके लिए मुख्य रूप से कम मार्जिन और निजी व्यापार की तुलना में स्थापना व्यय में वृद्धि, पेशेवर प्रबंधकीय कर्मचारियों की कमी और अनावश्यक हस्तक्षेप को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

विचार विमर्श

अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति रिपोर्ट, 1954 ने सहकारी ऋण के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण की सिफारिश की और अपने संचालन के क्षेत्र को बढ़ाकर, ग्रामीण बचत को प्रोत्साहित करके और अपने व्यवसाय में विविधता लाकर व्यवहार्य ऋण सहकारी समितियों की आवश्यकता पर जोर दिया।

समिति ने यह भी सिफारिश की कि सरकार को सहकारी समितियों की शेयर पूंजी में योगदान देना चाहिए। 1958 में, राष्ट्रीय विकास परिषद ने सहकारी समितियों पर राष्ट्रीय नीति पर एक संकल्प अपनाया। इसके बाद, जनवरी 1959 में, भारत सरकार के खाद्य और कृषि मंत्रालय द्वारा स्थापित सहकारी नीति पर कार्यकारी समूह ने ब्लूप्रिंट की सिफारिश की। तब से भारत सरकार ने राज्य सरकारों के माध्यम से सहकारी समितियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर वित्तीय, तकनीकी और प्रशासनिक सहायता प्रदान की है।

एक सहकारी को आम तौर पर अपनी सामान्य सामाजिक और आर्थिक जरूरतों औरध्या उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट व्यक्तियों के एक स्वायत्त संघ के रूप में देखा जाता है। यह देखा गया है कि कई स्थितियों में, इन सिद्धांतों का पालन सहकारी समितियों के लिए वर्तमान युग में वित्तीय व्यवहार्यता प्राप्त करने और बनाए रखने में एक बाधा बन जाता है, जो कि विनियमन, निजीकरण और वैश्वीकरण की विशेषता है।

इसे ध्यान में रखते हुए, कई उदारवादी सहकारिता अब इन सिद्धांतों की पवित्रता पर सवाल उठाती है, लेकिन कई रूढ़िवादी सहकारिताएं हैं जो इस बात पर कायम हैं कि संगठन के एक अलग रूप के रूप में सहकारिता के अस्तित्व के लिए ये सिद्धांत आवश्यक हैं।

इसके अलावा, एक विचारधारा भी है जो यह मानती है कि सहयोग के तीन आयाम हैं, अर्थात् आर्थिक, सामाजिक और नैतिक, जो इसकी सफलता के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। सहयोग का आदर्श वाक्य, प्रत्येक सभी के लिए और सभी प्रत्येक के लिए, वफादारी, विश्वास, विश्वास और फैलोशिप को दर्शाता है। एक सहकारिता सदस्यों की, सदस्यों के लिए और सदस्यों द्वारा एक पूर्ण लोकतांत्रिक संस्था है और यह निर्णय लेने की एक सदस्य–एक–वोट प्रणाली पर आधारित है।

एक व्यापारिक संगठन के रूप में सहकारिता कई मायनों में समान है और कई अन्य तरीकों से संगठनों के अन्य रूपों से भिन्न है। समानताएं भूमिकाओं और कार्यों के क्षेत्र में हैं और जिस तरह से भूमिकाएं और कार्य किए जाते हैं उसमें अंतर हैं। सहकारिताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने दिन–प्रतिदिन के व्यवहार में सहयोग के सिद्धांतों और मूल्यों को प्रतिबिंबित करें जो अन्य बातों के साथ–साथ समानता, इक्विटी और पारस्परिक स्वयं–सहायता पर जोर देते हैं।

किसी भी अन्य व्यावसायिक संगठन की तरह, सहकारी समितियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने संचालन में दक्षता और लाभप्रदता सुनिश्चित करें। लेकिन निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में अन्य व्यावसायिक संगठनों के विपरीत, एक सहकारी एक सामाजिक संगठन और एक व्यावसायिक उद्यम दोनों है और इसलिए, इसका दोहरा उद्देश्य हैय यह एक सामाजिक और साथ ही एक आर्थिक कार्य दोनों की सेवा करता है। एक सहकारी प्रबंधक को न केवल आर्थिक पहलुओं से बल्कि अपने संगठन के सामाजिक दायित्वों से भी संबंधित होना चाहिए।

सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियों में लोगों को शामिल करने, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों के संसाधनों और राजनीतिक शक्ति को जुटाने, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से स्थानीय नेताओं की पहचान करने और विकसित करने में, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज एकीकरण हासिल करने में संगठनों के अन्य रूपों पर उच्च तुलनात्मक लाभ है।

एक सहकारी संगठन के लिए आर्थिक औचित्य अपने सदस्यों के लिए आधुनिक तकनीक, बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच और पेशेवर प्रबंधन के लाभों को सुरक्षित करने के अपने प्रयास में निहित है। एक सहकारी संगठन जो इन लाभों को प्राप्त नहीं करना चाहता या नहीं कर सकता है, देर–सवेर असफलता के लिए अभिशप्त है। सैद्धांतिक रूप से, सामाजिक और आर्थिक विकास के दोहरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहकारिता की तुलना में शायद ही कोई बेहतर संगठनात्मक संरचना है, लेकिन अंतिम सफलता प्राप्त परिचालन दक्षता के स्तर पर निर्भर करती है।

अन्य संगठनों में सहकारी प्रबंधन और प्रबंधन के बीच प्रमुख अंतर यह है कि सहकारी समितियों को समस्या समाधान और निर्णय लेने में प्रमुख पदों पर निदेशकों, सदस्यों और कर्मचारियों को शामिल करने की अधिक आवश्यकता है। यह कोई छोटा काम नहीं है। पारंपरिक प्रबंधन विद्यालयों में प्रशिक्षित प्रबंधक, जब एक कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं, तो उन्हें लगता है कि उन्हें इसे अपने लिए सोचना चाहिए और एक समाधान खोजना चाहिए। यही उन्होंने प्रबंधन पाठ्यक्रमों में सीखा है।

सहकारी सिद्धांत को एक अलग प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। सहकारी प्रबंधकों से अपेक्षा की जाती है कि वे समस्या को सदस्यों और कर्मचारियों तक पहुँचाएँ और समाधानों के विकास में विभिन्न हित समूहों को शामिल करें। जटिल और विविध सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक वातावरण को देखते हुए जिसमें सहकारी प्रबंधक काम करते हैं और सहकारी समितियों के अधिकांश सदस्यों की गरीबी, अज्ञानता और निरक्षरता को देखते हुए, सहकारी प्रबंधकों को अपने समकक्ष व्यवसाय प्रबंधकों की तुलना में कहीं अधिक रचनात्मक, उद्यमी, मिलनसार और सदस्यों की जरूरतों और आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील होना।

उनके पास ग्रामीण उत्पादकों को संगठित करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए आवश्यक कौशल, निपुणता और दृढ़ता होनी चाहिए। इसके अलावा, उन्हें ग्रामीण लोगों के साथ सहानुभूति और सहानुभूति रखने में भी निपुण होना चाहिए, जो बेईमान जमींदारों, सूदखोरों, व्यापारियों और छोटे सरकारी अधिकारियों और पीढ़ियों से राजनेताओं द्वारा उनके शोषण के कारण स्वाभाविक रूप से संदिग्ध और भयभीत रहते हैं।

देश में कुल चीनी उत्पादन में सहकारी समितियों का हिस्सा 60 प्रतिशत से अधिक है और ब्रांड नाम के तहत विपणन किए जाने वाले खाद्य तेल का लगभग 50 प्रतिशत है। वे देश में कुल गेहूं खरीद के 27 प्रतिशत और कुल जूट खरीद के 21 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार हैं। वे कुल ग्रामीण उचित मूल्य की दुकानों के 26 प्रतिशत के स्वामी भी हैं।

1904 में अपने जन्म के बाद से, भारत में सहकारी समितियों ने एक लंबा और कठिन रास्ता तय किया है। उन्होंने कुछ जगहों पर अच्छा प्रदर्शन किया है और कई जगहों पर खराब। लेकिन तथ्य यह है कि उनमें से अधिकांश जीवित हैं, यद्यपि ऑक्सीजन की भारी खुराक के साथ, 90 से अधिक वर्षों तक और किसी के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि वे सभी निकट भविष्य में मर जाएंगे। इसलिए उनके प्रदर्शन और इसे प्रभावित करने वाले कारकों की जांच करना हमारे समय और ऊर्जा के लायक है।

जहां तक सहकारी समितियों के प्रदर्शन के निर्धारकों का संबंध है, विचार के तीन अलग–अलग स्कूल हैं। एक, जिसे संरचनावादी कहा जा सकता है, का मानना है कि यह मुख्य रूप से एक सहकारी की रणनीति और संगठनात्मक संरचना है जो काफी हद तक इसके प्रदर्शन – सफलता या विफलता को निर्धारित करता है।

निष्कर्ष

ऐतिहासिक रूप से, भारत में सहकारिता समाज के वंचित वर्गों के आर्थिक और सामाजिक शोषण के जवाब में उभरी। उनका मुख्य उद्देश्य शोषण को कम करना और इस प्रकार अपने सदस्यों की स्थिति में सुधार करना थाय लाभ को अधिकतम करना कभी भी प्रमुख लक्ष्य नहीं रहा। नए परिवेश में, सहकारी समितियों को बिना किसी सरकारी संरक्षण और समर्थन के अपने दम पर अन्य प्रकार के संगठनों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी।

संगठन के रूप में सहकारिता दुनिया के विकसित और विकासशील दोनों देशों में व्यापक रूप से प्रचलित है। उन्हें भारत सहित विकासशील देशों में ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। 1904 में अपने जन्म के बाद से, भारत में सहकारी समितियों ने एक लंबा और कठिन रास्ता तय किया है। अब, वे अपनी सदस्यता, व्यापार टर्न ओवर, और अपने सदस्यों के सामाजिक–आर्थिक कल्याण में योगदान और इसलिए ग्रामीण विकास के मामले में भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

संदर्भ

1. सिंह, कटार और वीरेंद्र पी. सिंह (2018) भारत में डेयरी डेवलपमेंट रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रॉस्पेक्ट, रिसर्च पेपर 15, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, आनंद

2. सिंह, लोटन और जे. चटराज (2016) डेयरी सहकारी समितियों की सेवा के माध्यम से पारिवारिक श्रम आय में वृद्धि, इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, 51(4)

3. सूर्यवंशी, एस.डी. और एन.एस. गायकवाड़ (2016) एकीकृत ग्रामीण विकास में वाराना सहकारी चीनी कारखाने का प्रदर्शन और उपलब्धियां एक केस स्टडी, इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, 51 (4)

4. तैमनी, के.के. (2014) इंटीग्रेटेड को–ऑपरेटिव्स द केस ऑफ शुगर को–ऑपरेटिव्स इन महाराष्ट्र, के.के. तैमनी एशिया की ग्रामीण सहकारी समितियाँ। नई दिल्लीरू ऑक्सफोर्ड एंड आईबीएच पब्लिशिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड

5. तिवारी, एस.के. (2016) सहकारी समितियों की वित्तीय भेद्यतारू कुछ नीतिगत प्रभावों के लिए अंतर्निहित कारणों का विश्लेषण, भारतीय कृषि अर्थशास्त्र जर्नल, 51 (4)

6. तिवारी, एम.एम. (2015) इंटीग्रेशन ऑफ फिशरीज एंड फिशरीज को–ऑपरेटिव्स इन बिजनेस डेवलपमेंट इन द न्यू मिलेनियम, द कोऑपरेटर, 38(8), फरवरी

7. वैद्यनाथन, ए. (2016) कृषि विकासरू संस्थागत सुधार की अनिवार्यताएं, आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, विशेष संख्या, सितंबर, पीपी। 2451–2458

8. वरदे, पी. संगीता और बी.डी. भोले (2016) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में सहकारी कताई मिलों का प्रदर्शन और संभावनाएं, भारतीय कृषि अर्थशास्त्र जर्नल, 51 (4)